पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 37 | प्रति सोमवार इंदौर, 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

आखिर गाजा के बाद इजरायल पर ईरान का हमला

ब्रिटेन-अमेरिका के साथ जॉर्डन-सऊदी का सीधा सहयोग इज़राइल को

ईरान व चीन ने रूस को, यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी टैंको व विमानो को नष्ट करने सीधे ड्रोन व सैन्य सहायता पहुंचाई थी। जबकि इजरायल के विरुद्ध गाजा के लड़ाको को भी ईरान सैन्य सामग्री हथियार आदि सतत आपूर्ति कर रहा है। 14 दिन पहले इजरायली विमानो के हमले में ईरानी संघ अधिकारी मारा गया था तब से ही ईरान लगातार इजरायल को बदला लेने युद्ध की धमकी दे रहा था। आज ईरान ने इजरायल हमला कर दिया।

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियो ने विभिन्न षड़यंत्रो के माध्यम से लगभग पिछले 100 सालो से दुनिया पर अपना कब्जा करने सरकारो को खरीद कर अपने कानून बनवा थोपने जनता का शोषण करने बढ़ती आबादी को खत्म करने के लिये जो विश्व शैतान संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, व उसके जुड़े व संरक्षित संगठनो जो सबसे घातक षड़यंत्रकारी विश्व घातक संगठन एवं विश्व आतंकी व्यापार संगठन के माध्यम से अपना घातक विषैला खाद्य पदार्थ औषधियां मशीन दवाइयां इंजेक्शन आदि का माल बेच मोटी कमाई करने के साथ वहां पर कब्जा करना और उनकी जनसंख्या को घटाने के लिए जो टीके बेचने का षड्यंत्र किया उससे पूरी दुनिया के अधिकांश देश भूख बेरोजगारी बीमारियो से हैरान परेशान है। उनके लिए पूर्णता अमेरिका उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व घातक संगठन के साथ चीन व ब्रिटेन अगर ये तीनो देश युद्ध भड़क कर अगर पूरी दुनिया में फैल जाए और यह तीनो देश नष्ट हो जाए तो आने वाले 100 वर्षो तक दुनिया के अधिकांश देशो की आबादी चैन से रह सकेगी।

ईरान इजरायल गाजा यूक्रेन रूस का युद्ध सतत 6 महीने मे फैल कर इस युद्ध में खुलकर परमाणु बमो का उपयोग किया जाए। अमेरिकन स्कूल सालो मे जिन देशो कोहैरान परेशान कर नाटो में शामिल किया है वह सब मिलकर अमेरिका को औरब्रिटेन ने जिन देशो पर राज किया है उसके 55 सारे देश मिलकर ब्रिटेन को अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने मिलकर आक्रमण कर देवर्णाशत कर देतो नाटो के सारे देश अमरीकी चंगूल से और ब्रिटेन के सारे 55 कॉमनवेल्थ के देश जिनको इन डकैत चोर नीचो ने उन देशो मे घुसकर दुशासन भी किया लूट खसोट की, के साथ इसाई षड्यंत्रकारियो ने वहां की धर्म, संस्कृति, ज्ञान विज्ञानसबको नष्ट करअपने ईसाई धर्म फैलाने के साथ जाते समय उनसे पेट की आजादी कि दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवा लिए दिन कर काटो ने 55 देश को नोट वसुता उनसे वह अभी भी डॉलर पेट की रकम के रूप मे हर साल गुजरते हैं इसलिए इन सारे देशो को चाहिए कि जैसे ही युद्ध सीधे ईरान अमेरिका-चीन रूस -ब्रिटेन मे शुरू होतो सारे 55 देश ब्रिटेन से और सारे नाटो के देश जिनके यहां अमेरिका ने अपने हथियार जमा कर रखे हैं और वहां पर अपनी सेनाओ को रखकर उनसे खर्चा बसुलता है। ईरान रूस चीन के साथ मिलकर सभी सदस्य नाटो देश अलग होकर अमेरिका पर ही आक्रमण कर उसको और उसकी षड्यंत्रकारी कंपनियां जिसमे फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट टेस्ला गूगल वॉलमार्ट अमेजॉन फाइजर हथियार उत्पादक पेट्रो दवाई औषधियां टीके उत्पादक सभी कंपनियो को नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

पूरी दुनिया के मात्र ये तीन राष्ट्रो अमेरिका ब्रिटेन और चीन को खत्म कर दे। विश्व की बेरोजगारी भुखमरी बीमारियां अगले 100 साल तक समुद्र के तल मे आराम करते हुए जनता को चैन से जीने का अवसर देगी। अकेले भारत के 80 करोड़ बेरोजगार भुखमरी से त्रस्त बीमा रु.1 किलो का गेहूं का चावल खाने वाले लोग अगर यह प्रार्थना करें कि रूस के साथ सारे अमेरिका के नाटो, ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ के वह पिछले 25-30 वर्षो मे चीन ने जिन देशो को कर्ज में उलझा कर उनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट की है वह सब एक साथ एकजुट हो मिलकर अमेरिका ब्रिटेन के साथ चीन का भी नाम अनुसार धरती से मिटा दे या उसकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन चौपट करते हैं।

तो न केवल विश्व की मानव आबादी वरन पशु पक्षी वनस्पतियां जन जल जंगल जमीन जलवायु सब आने वाली 5 से 10 पीढ़ियां के लिए शांति के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है अगर हमारे देश को युद्ध मे कूदने की जरूरत पड़ी तो इंसान दल वीडियो झूठ पार्टी के चुटकुले को संसद में ही नष्ट हो जाना चाहिए यह ज्यादा बेहतर होगा।

अन्यथा अगर पुनः शाह मोदी की सरकार आ गई तो मोदी तो मोटे कमीशन के बदले में पूरा उत्तरी भारत देश में कश्मीर सिक्किम लद्दाख तिब्बत से लेकर असम अरुणाचल प्रदेश मेघालय सब मोदी चीन को थाली में सजा देने पर तुला ही हुआ है। फिर चीन से भारत ही नही वरन् उसके सीमाओ से लगने वाले सभी 16 पड़ोसी देश अभी उसकी हड़प्पा नीति से परेशान है। बेशक उसने पूरी दुनिया के हर देश को अपने सस्ते माल, मोटे कर्ज के मकड़ जाल में उलझाने के साथ वन बेल्ट वन रुट की मकड़ जाल में भी उलझा रखा है। इसलिए चीन को नष्ट होना आवश्यक है।

युद्ध की है शुरुआत दुनिया के अन्य देशो के लिए चीन और अमेरिका की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लूट डकैती षड्यंत्र और गुलाम बनाने की चालो को ठंडा करने में काफी उच्च भूमिका निभाएगा।

भारतीय चुनाव आयोग से निर्वाचन अधिकारी तक सभी कर्मचारी-अधिकारी जालसाज

ईमानदारी से निर्वाचन अधिकारी कार्य करें तो सत्ताधीश दल के सभी उम्मीदवार अयोग्य

प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सभी दलो के उम्मीदवार भरते हैं झूठी जानकारिया सब को न्यायालय में सबूत पेश कर रद्द करवा सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग अपने आप मे स्वयं ही पूरा सत्ताधीशो का रखेला कठपुतली ही घोर भ्रष्ट जालसाज अधिकारी ही होता है। उसके सत्ताधीशो के चरण चाटने घोर जालसाज भ्रष्टाचार करना ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है और इसी योग्यता के आधार पर उसको चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयुक्त के पद पर बैठाया जाता है। वहां से लेकर राज्यो के चुनाव आयुक्त और जिलो मे बैठे कलेक्टर जो सट्टा ढिशुम की कठपुतली बनकर नाचते हैं सबको भ्रष्ट जालसा चालबाज होते हैं और जितने भी चुनाव कार्य मे लगे हुए कर्मचारी अधिकारी होते हैं। सब आंख मीच कर ऐसी व्यवस्था को पूरी हवा देते हैं। चुनाव नामांकन फॉर्म भरने मे ही अधिकांश सत्ताधीश व राजनीतिक दलो के बड़े उम्मीदवार जानकारी के मामले मे चल अचल

संपत्ति निवेश की सारी जानकारीयां झूठी भरी जाती है और मेरे कथन की सत्यता की पुष्टि के लिए उन उम्मीदवारो के मात्र 6 महीने के पुराने सारे फोन की कॉल रिकॉर्डिंग निकाल कर सत्याता की पुष्टि की जा सकती है। निर्वाचन अधिकारी यह जानकर भी किया जानकारियां झूठी है अधूरी हैंउन सब के फार्म स्वीकार कर लेता है जैसा कि अभी हाल ही में हेमा मालिनी ने मथुरा के निर्वाचन अधिकारी को अपने फार्म में अधिकांश जानकारियां खाली छोड़कर जमा कर दिया और उसको स्वीकार कर लिया गया। जबकि दूसरी तरफ खुजराहो मे जानबूझकर हरामखोर कलेक्टर नही जबकि उम्मीदवार ने फार्म अपने वकील से भरवारा था फिर उसे वकील के बाद में निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय मे कार्य करने वाले दो-तीन जो बड़े अधिकारी होते हैं वह फॉर्म की जांच करते हैं जब उन्होंने फॉर्म की जांच की कलेक्टर ने फार्म की जांच की तो फार्म स्वीकार करने से पहले उसमे अगर कमियां थी तो देख कर बाहर क्यो नही किया गया परंतु जानबूझकर जेपी नड्डा को जीतने के लिए खजुराहो सीट से उसने सपा की उम्मीदवार का नामांकन पत्र ही रद्द कर दिया यह पूरी जलसा जी का जीता जागता उदाहरण है

(शेष पेज 2 पर)

10 साल में झूठे वादों से जीत जनता व देश को तबाह किया

10वर्षो का इतिहास भविष्य में भी दोहराओगे वाचाल की गारंटी

बहुराष्ट्रीय कंपनी व पूंजीपतियों से मोटा कमीशन खा बेरोजगारी भुखमरी बीमारी दी जनता को अब क्या कपड़े उतरवा कटोरा दोगे?

सन 2014 मे उसे हुआ आचार्य मोदी ने जनता को अच्छे दिन 15 लाख 2 करोड़ रोजगार सबको मकान का वादा कर चुनाव जीत और जीतने के साथ ही युसूफ उसने मोटा चंदा लिया था। अमेरिकी षड्यंत्रकारी संगठनो विश्व घातक व आतंकी व्यापार संगठन की दानदाता बहुराष्ट्रीय कंपनियों अमेजॉन वॉलमार्ट अपने पूंजीपति मित्रों अडानी अंबानी टाटा बिरला मित्तल वह सैकड़ो अन्य से और चीन से मोटा कमीशन खाकर उनको लाभ पहुंचाने के लिए, सफाई के नाम पर सड़को पग मार्गो ठेलो पर व्यापार करने वाले लगभग 2 करोड़ लोगो को बेरोजगार कर घर बैठा दिया। जिसे 20 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर आ गए। बाद मे उनका मोटा लाभ पहुंचाने केशलेस नोटबंदी जीएसटी तालाबंदी से लगभग एक करोड़ से ज्यादा छोटी-मोटी इकाइयां दुकान उद्योग जिनमे 30 करोड लोगो को रोजगार मिला हुआ था सभी बेरोजगार हो गए। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक को तीन किस्तो मे 50 लाख करोड़ से भारतीय जीवन बीमा निगम को2 लाख करोड़ से उसके लाभ के नाम पर सभी वित्तीय संस्थाओ स्टेट बैंक से लेकर सभी राष्ट्रीयकृत बैंको को अपने मित्रो का छोटा, मोटा, वृहद लगभग देश-विदेश मे 40 लाख करोड़ का धन माफ करवानेनए उद्योग लगाने विदेश मेंथान लगाने के नाम पर बर्बाद कर दिया गया। इसके साथ ही रेल तेल मेल बेल सेल गेल हाल बैंक बीमा हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन बंदरगाह सबको आपके अपने आप की जागीर समझ हरामखोर ने अपने मित्रो को अंतरित कर दिया और उसके बाद मे भी वाचाल जनता को अगला चुनाव जीतने के लिये गारंटी दे रहा है। अगर जीत गयातो निश्चित ही सभी सरकारी शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, विद्युत कंपनियां, सड़के, रेलवे, सारी सरकारी उपक्रम बचे हुए रेलवे स्टेशन बंदरगाह हवाई अड्डे सबको निजी क्षेत्र मे देकर जनता को बेरोजगारी भुखमरी बीमारी बांटने के साथ उनके शरीर का मांस भी नोचने का षड्यंत्र कर सकता है। समझदार जनता न केवल अपनी बल्कि आने वाले बच्चो के भविष्य की अगर सच मे चिंता करता है तो कदापि कमल के फूल को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल मानकर वोट देने की तो दूर देखने की भी कोशिश ना करे।

(शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

भारतीय चुनाव आयोग से निर्वाचन अधिकारी तक सभी कर्मचारी-अधिकारी जालसाज

पेज 1 का शेष

आखिर ऐसे कलेक्टर को तत्काल वहां से हटकर और उसके ऊपर जांच आयोग बिठाकर हटाया क्यों नहीं गयाकि उसने इतनी महत्वपूर्ण उम्मीदवार के नामांकन पत्र को स्वीकार करते समय उसमें कमियां नही देखी और जानबूझाकर अंतिम समय में उसका फॉर्म को रद्द कर दिया यह कोई छोटी-मोटी गलती नहीं थी। अगर यही गलती ही नही सही भी नरेंद्र मोदी के नामांकन फार्म में जबकि उसने पिछले दो फार्मों में उसकी पत्नी होते हुए उसे पत्नी के फॉर्म को खाली रखा नामांकन रद्द किया जाना चाहिए था पर नहीं किया गया यह जालसाजी का उत्कृष्ट उदाहरण है कहानी नामांकन फार्म की शुरू होने के बाद और भी बड़ी हो जाती है विपक्ष के उम्मीदवारों के सहयोगियों या उनसे संबंधित लोगो की गाड़ियों की जांच होती है उसमें धन पाया जाता है पर वही काम सत्ताधीश पक्ष के लोगो की गाड़ियों की जांच भी नहीं होती उनके यहां शराब कबाब सब गाड़ियों में ढोल जाते हैं पर उनकी गाड़ियां नही पकड़ी जाती दूसरी तरफ सभी सत्ताधीश उम्मीदवार जो कम से कम 25 50 करोड़ के मालिक होते हैं पर अपनी अचल संपत्ति में मात्र कुछ लाखो की संपत्ति दिखाई जाती है वही हाल शिवराज सिंह चौहान ने अपने फार्म में किया जो आदमी 20 साल लगातार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा उसके पास मात्र लाखों की संपत्ति थी जबकि वह हजारो करोड़ के पिछले तीन तीन मुख्यमंत्री कॉल में गबन कर चुका हैवह बात दूसरी है कि भ्रष्टाचार के चलते उसके गबन की जांच नहीं हुई वरना चिरायु मेडिकल कॉलेज से लेकर तालाब के किनारे तालाब सुखाकर तालाब की जमीन पर बना हुआ होटल से लेकर उसके होटल विदेश में भी खड़े हुए हैं पर ना यह बात स्वयं ना उसने बताई न चुनाव आयोग ने उठाई और ना ही फाकारों ने, न विपक्ष ने, ऐसे साथ ही उसके ऊपर बुधनी होशंगाबाद से लगातार रेत की चोरी करते रहे हैं। और बड़ा नेता बनने के लिए दुनिया जानती है बड़ा मोटा धन अवैध कार्यों व व्यवसाय से ही एकत्रित किया जाता हैकलेक्टरजो सक्षम है कि वह कम से काम अचल संपत्ति ऐसे-ऐसे उम्मीदवारों के नाम से न होकर उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से होती है जो उसने अपने सत्ता में रहते कमाई हुई होती हैवह जिलो की कलेक्टर की नजर में होने के बावजूद भी उसे जानकारी को वह सार्वजनिक नहीं करते जबकि आम आदमी की जानकारी कोपैन कार्ड से आधार कार्ड से जोड़कर उसके बिजली का बिल जमाना होने पर भी उसके फार्म को रोक दिया जाता है बड़े-बड़े दलो के उम्मीदवारों के मामले में यह सारी दाल साजियां हरामखोर जिलो में बैठा हुआ कलेक्टर शहर जिला निर्वाचन अधिकारी चुपचाप स्वीकार कर लेता है और इस जलसा जी और स्वतंत्रता के लिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के अंतर्गत हर कलेक्टर पर मुकदमा चलाकर सबकी नौकरी खत्म की जानी चाहिए। मैंने स्वयं दो चुनाव 2014 और 2019 के लड़े। 2014 में सुमित्रा महाजन उम्मीदवार के रूप में खुले में सरकारी संपत्तियों के सार्वजनिक बगीचों में सभाएं करती रही और हर सभा पर 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा भोजन पानी टेंट आदि में खर्च हुआ किसी ने नहीं दिखाई वही हाल शंकर लालवानी का था पर उसके बारे में भी सब चुप रहे खर्च दिखाने के टाइम पर भी यह 50 से ज्यादा करोड़ो रुपए खर्च करते हैं। शहर भर में झंडा-बैनर की लंबाई चौड़ाई नापने नाश्ता करवाने लाखो लोगो को खर्च किए जाते हैं परंतु वहां बैठे खाता नियंत्रक चुपचाप मोटा पैसा लेकर उनके सर झूठ स्वीकार करते रहते हैं उन सब की भी नौकरी खत्म की जानी चाहिए कि वह हरामखोर बड़े राजनीतिक दलो के सारे पापो को पुण्य बना देते हैं और छोटे उम्मीदवारों की छोटी-छोटी सी चीजो के खर्चों को लेकर महीना तक परेशान करते हैं। जो परीक्षा पर्यवेक्षक इस दूसरे राज्यों से हर उम्मीदवार के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं वह हरामखोर पर्यवेक्षक बदमस्त होटल में सुरा सुंदरी का सेवन करते हुए पड़े रहते हैं जिनके खर्च जिले का आबकारी अधिकारी उठाना है उसके उन खर्चों के नाम से लोक निर्माण विभाग नगर निगम पालिकाएं भी खर्च दिखती हैं और एक आदमी की खर्चों को तीन जगह दिखाकर तीनो विभाग पैसा हजम करते हैं इसी सब्जेक्ट रहते हैं और जानबूझकर पर्यवेक्षकों को सुर सुंदरी वह गाड़ियां उपलब्ध करवा कर पूरे समय तक उनको बाहर दर्शनीय स्थलों तीर्थ क्षेत्रों अभ्यारणो पर्यटन स्थलों पर घुमाया जाता रहता है और वह थैले भर का काम पर्यवेक्षक नही करता।

जबकि उसे अपने चुनाव के हर क्षेत्र में न केवल घूमना चाहिए बल्कि कौन सा उम्मीदवार कितने पोस्टर बैनर कितनी बड़ीलाकर कहां पर भाषण बाजी कर रहा है मंत्र सजा रहा है उसके ढोल ताशे बज रहे हैं और क्या भाषण दे रहा है वहां तक की उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए उसके साथ ही उसकी टीम में काम करने वाले और चुनावी क्षेत्र के नाको पर बैठे रहने के साथ उम्मीदवार के वीडियो सभी प्रकार की अवैध शराब सामग्री धन आदि की भी जांच करनी चाहिए परंतु वह सारी जांच केवल विपक्षी नेताओं के लिए की जाती है और सत्ताधीश दल के नेताओं के लिए सब सारे अपराध माफ होते हैं। क्योंकि सत्ताधीश दल का नेता जो उम्मीदवार है, को अनेको स्रोतों से धन प्राप्त होता रहता है। वह धन खुलकर पानी की तरह बहाता है।

यह सारे खर्चे छोड़ भी दिए जाएं तो आखिर अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन हर मतदान केंद्र पर सत्ताधीश दल का उम्मीदवार एक से रु. 200000 खर्च करता है हर मतदान पर उसके बीस से 30 नेता रु वो रु. 2000 देता है। लगभग 200 से ज्यादा भोजन के पैकेट प्रति पैकेट के यदि रु.100 भी मान लिये जाएं। तो 20000 इसी के हो जाते हैं दिन भर में करीबन 500 चाय की व्यवस्था की जाती है प्रति चाहे रु.10 की होती है 5000 की हो जाती है। टेंट तंबू टेबल आदि का खर्च 5000 भी मान लिया जाए। तो प्रति मतदान केंद्र डेढ़ से रु.2 लाख खर्च किए जाते हैं। लोकसभा सांसद के लिए 2300 मतदान के दो में रु 23 करोड़ खर्च हो जाते हैं। वही हिसाब जिस दिन मतगणना की जाती है। उसे दिन भी लगभग इतना ही खर्च 200 से ज्यादा एजेंट बैठाये जाते हैं। अर्थात सत्ताधीश दल का उम्मीदवार करोड़ो में खर्च करता है और लाखों में दिखता है उसके हिसाब को अपना पर्यवेक्षक देखा है ना खाता देखने वाले जो एजेंट बैठा ले जाते हैं वह देखते हैं बस जो निर्दल उम्मीदवार होते हैं उन्ही को यह हरामखोरो की फौज जो जिलाधीश कार्यालय में बैठी रहती है हर दिन परेशान करके वही गिर के रखती है ताकि वह चुनाव प्रचार ही नही कर पाएं।

दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं व अन्य जनता को भी चाहिए कि वह है हरसट्टा दी दल की उम्मीदवार पर कहां कौन कितना खर्च कर रहा है कौसी रैली निकाल रहा है कैसा मंच लगा रहा है। वीडियोग्राफी कर यह सारे सबूत इकट्ठे कर जनता का कोई आदमी नहीं न केवल उम्मीदवार के विरुद्ध बल्कि जिलाधीशों से लेकर उनका प्रचार करने वालो पर्यवेक्षक केंद्र वा राज्यों के चुनाव आयुक्त आदि के विरुद्ध 120 ऐ वा बी, 420 467, 68, आदि में जिला न्यायालय में प्रकरण फाइल करन केवल चुनाव रद्द कार्रवाये बल्कि इन सारे अधिकारियों को भी न्यायालय में घसीट ले जहां पूरे देश में ऐसे उम्मीदवारों के विरुद्ध अगर 2500 कैसे भी पूरे देश में लगा दिए जाएंगे और 10 20 25 को भी सजा हो गई 10 20 25 के चुनाव रद्द हो गएतो यह सारे हरामखोर जलशा आज सारे काम बड़े दर दर को ईमानदारी से करना शुरू कर देंगे तब ही चुनाव ईमानदारी से होने और उम्मीदवारों के विधान व लोकसभा में पहुंचकर सही ढंग से काम करने की उम्मीद की जा सकती है।

जैसे मोदी ने देश के बड़े-बड़े पत्रकारों पक्ष विपक्ष के नेताओं के लिए इजराइल के पेगासास सॉफ्टवेयर का जासूसी के लिए उपयोग किया, जो पूर्णता: असंवैधानिक व अवैध था। कभी इस देश के पर्दे के पीछे के असली राक्षस खुदाओं जो केंद्रीय व राज्य सरकारों के मंत्रालयों से लेकर जिलो के कलेक्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो निर्वाचन कार्यों को संपन्न करवाते हैं। जो धन केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में सीधे जिले के अधिकारियों के संबंधित विभाग के प्रभारी व हितग्राहियों के खाते में पहुंचाने लगे हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी बैठे हैं। जो घोर भ्रष्ट अय्याश जालसाज हरामखोर मक्कार जो सभी प्रकार के माफियाओं को पालने वसूली करने व जनता के धन को विभिन्न षड्यंत्रों से हजम करने करवाने और भ्रष्टाचार करने के लिए जिम्मेदार हैं। इनके भी मोबाइल टेप कर जासूसी क्यों नही करवाई जाती। जिसका शासकीय कार्यों में पारदर्शिता के लिए सरकार को हक है।

इसके साथ ही केवल विपक्ष के उम्मीदवारों नेताओं का ही फोन क्यों टैप करके उसमें उनसे मिलने जुलने वाले तक के नंबर नाम बातचीत आदि टेप किए जाते हैं।उन नंबरों पर संबंधितों को डराया धमकाया जाता है। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2014 और 19 में मेरे साथ हुआ। और उनके व्यक्तिगत स्तर पर किए गए मोटे भ्रष्टाचार व कमाई के षड्यंत्र की वह मोबाइल टेपिंग सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती। ताकि जनता जान सके कि उनके जिले का कलेक्टर से लेकर देश की असली खुदाओं की सच्चाई क्या है और वह कितने ईमानदार हैं?

दूसरी तरफ पत्रकारों से लेकर आम जनता को लगातार धमकाया जा रहा है पिछले 10 सालों से कि आपने मोदी के खिलाफ बोला या लिखा तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कलेक्टर कमिश्नर मोदी व अन्य नेताओं के बाप की जागीर है। संविधान और उसमें दी हुई जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता व गोपनीयता की रक्षा करने का दायित्व सरकार का है उल्टा ही वह उसके कर्मचारी अधिकारी कोई भी मोदी का सच नही बोलेगा अगर सच बोलेगा तो उसके मोबाइल में घुसकर उसकी रिकॉर्डिंग निकाल कर उसको गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया जाएगा बार-बार धमकाया जा रहा है और कोई भी निकम्मा विपक्ष का नेता या बड़े समाचार पत्र इन सब बातों को लेकर जिला व सत्र न्यायालय में कोई भी मुकदमा दर्ज नही करवाते। यही हमारी नपुंसकता जालसाज भारतीय प्रताणना सेवा अधिकारियों को अपने बल उसके अधिकारों के अहंकार का तांडव करने की पूरी छूट देती है।

इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासा

घाटे में चल रहीं 33 कंपनियों ने डोनेट किए 582 करोड़, अकेले भाजपा को मिला 434 करोड़ रुपये

इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद इसे लेकर हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. बॉन्ड से जुड़ा ऐसा ही एक राज फिर से सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि 33 ऐसी कंपनियों ने चुनावी चंदा दिया, जो खुद घाटे में चल रही थी. इलेक्टॉरल बॉन्ड के डाटा के जरिए 45 ऐसी कंपनियों का पता चला है, जिनके पैसे का सोर्स संदिग्ध पाया गया है. पिछले कुछ सालों में इन कंपनियों ने भर-भरकर राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग दी है. अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, संदिग्ध पैसे के सोर्स वाली इन 45 कंपनियों को ए, बी, सी और डी कैटेगरी में बांटा गया है. ए कैटेगरी में शामिल 33 कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 576.2 करोड़ रुपये का चंदा दिया. इसमें से 434.2 करोड़ रुपये (कुल दान का 75%) सीधे बीजेपी के पास गए हैं. पार्टी ने इनके जरिए मिले बॉन्ड को इनकैश किया है. इन कंपनियों की 2016-17 से 2022-23 तक सात सालों में टैक्स लगने के बाद कमाई लगभग जीरो हुई है.

एक लाख करोड़ के घाटे में रहीं 33 कंपनियां

रिपोर्ट में बताया गया कि इन 33 कंपनियों का कुल घाटा 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का है. ए कैटेगरी में शामिल 33 में से 16 कंपनियों ने कभी टैक्स भी नहीं भरा है. घाटे में चल रही इन कंपनियों के जरिए किया गया दान बड़े घोटाले का इशारा कर रहा है. इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ये कंपनियां अन्य किसी बड़ी कंपनी के लिए मुखौटे का काम कर रही थीं या फिर इन्होंने अपने लाभ और घाटे की गलत जानकारी दी है. इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की भी संभावना जताई जा रही है.

छह कंपनियों ने मुनाफे से ज्यादा किया दान

बी कैटेगरी में छह ऐसी कंपनी भी हैं, जिन्होंने 646 करोड़ रुपये दान किए गए हैं. इसमें से 601 करोड़ या कहें 93 फीसदी बीजेपी के पास गए हैं. 2016-17 से 2022-23 के बीच इन कंपनियों को लाभ भी हुआ है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना दान किया गया है, वो

उनके लाभ से भी ज्यादा है. ऐसे में इन कंपनियों को लेकर संदेह जताया गया है कि ये भी किसी के लिए मुखौटे का काम कर रही हैं या फिर इन्होंने घाटे और लाभ की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.

इलेक्टोरल बॉन्ड की सी और डी कैटेगरी में कितनी कंपनियां?

सी कैटेगरी में तीन कंपनी शामिल हैं, जिन्होंने 193.8 करोड़ रुपये का दान दिया. इसमें से 28.3 करोड़ यानी 15 फीसदी इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी ने भुनाया. बाकी का 91.6 करोड़ रुपये या कहें 47 फीसदी कांग्रेस, 45.9 करोड़ रुपये (24 फीसदी) टीएमसी, 10-10 करोड़ रुपये (लगभग पांच फीसदी) बीआरस और बीजेडी को मिला. 7 करोड़ रुपये AAP को मिले हैं. तीनों कंपनियों का मुनाफा पॉजिटिव रहा है, लेकिन इनके जरिए टैक्स चोरी किए जाने की संभावना जताई गई है. डी कैटेगरी में शामिल 3 कंपनियों ने 16.4 करोड़ रुपये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान किए. इसमें से 4.9 करोड़ (30 फीसदी) बीजेपी को मिले, जबकि कांग्रेस को 58 फीसदी चंदा हासिल हुआ. अकाली दल और जेडीयू को कुल चंदे का 6.1 फीसदी मिला. इन कंपनियों के न तो मुनाफे की जानकारी है और न ही इनके जरिए भरे जाने वाले टैक्स की. माना जा रहा है कि शेल कंपनी बनाकर इनके मालिकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का प्रयास हुआ है.

मप्र लोक स्वास्थ्य भ्रष्ट तांत्रिकीय, जल निगम नगरीय संस्थाएं पी जाती हैं 50% जन जल

हर साल हजारों करोड़ की बर्बादी के बाद भी जनता प्यासी

क्यों जमे हैं वर्षों से अधिकारी, चुनावी आचार संहिता में भी स्थानांतरण क्यों नहीं किया?

मध्य प्रदेश मे केंद्र एवं राज्य पोशाक योजना के अंतर्गत 2024 तक गांवो व शहरो के हर घर मे नल जल योजना के साथ, ग्रामीण पेय जल, जल जीवन मिशन मे, बस हाथो मे पेयजल व्यवस्था की स्थिति, गुणवत्ता प्रभावित बस्ती मे कार्य ग्रामीण शिक्षण शालाओ एवं आंगनवाड़ियो मे जल प्रदाय, आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाति उप योजना, गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्रोतो वाली भाषाओं की योजनाओ का विवरण, फ्लोरोसिस नियंत्रण, खारेपन के नियंत्रण की योजनाएं, लोह तत्व की अधिकता का निराकरण, भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम आदि कार्यक्रमो मे लगभग 50 से 60 हजार करोड रुपए प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश को मिलते हैं यहां पर भीइन योजनाओ मे लूट करने के लिए जल निगम की स्थापना की गई है जिसमे सारे चुन-चुन कर ऐतिहासिक अन्य विभागों से सिविल सिविल इंजीनियरिंग के कार्यरत एवं सेवा निवृत्त भ्रष्टो को बैठाला गया है। जो हजारो करोड़ के टेंडर घोर जालसाज मेघा इंजीनियरिंग एलएनटी आदि को मोटे कमीशन पर दिए गए हैं।

वर्तमान मे इंदौर मे ही देखे तो नर्मदा जल आपूर्ति मे पिछले 10 सालो से ज्यादा समय से बैठा संजीव श्रीवास्तव जिसका पिछली बार सन 2019 मे स्थानांतरण कर दिया गया था जो पुनः जनवरी 2019 मे इंदौर मे आकर बैठ गया जिसने सैकड़ो करोड़ की द्वितीय व तृतीय चरण की साढे चार सौ एमएलडी पानी नर्मदा से उठाकर इंदौर मे विचलित किया गया इन योजनाओ के बनने के पहले कहा गया था की इंदौर की पूरी जनता को पूरे 24 घंटे पानी मिलेगा। परंतु 540 एम पानी आने के बाद मे भी इंदौर की 40% जनता को आज भीहर दिन 1 घंटे जलापूर्ति नही मिल रही है। जिनको वर्तमान मे 2 दिन मे आधा घंटे अर्थात महीने मे 7:30 घंटे ही पानी मिलता है उसके 360 रुपए वसूली की जाती है दूसरी तरफ 10% जनता ऐसी भी है जिसे सालो से नर्मदा का पानी नही मिला इसके बावजूद भी उसको डरा धमका कर बुलबुली की जा रही हैऔर उन सबके लिए जिम्मेदार है जो 10 वर्षो से ज्यादा समय से कुंडली मारे बैठ संदीप श्रीवास्तव जो हर साल लगभग एक अरब रुपए लाइनो के रख रखाव पंप को सुधारने आदि मे खर्च कर 50% हजम कर लेता है बेशक इसका हिस्सा संभाग आयुक्त जिलाधीश निगम आयुक्त से लेकर नीचे तक बंटता है।

बेशक पहले जानबूझकर जल का संरक्षण नही किया जाता। बरसात खत्म होनेके दो-तीन महीने बाद नवंबर दिसंबर से ही जानबूझकर शहर में बनी हुई टांग क्यो की पूरी मारी नहीं की जाति और टैंकरो का कारोबार शुरू कर हर महापौर पार्षदो से लेकर जल आपूर्ति मे बैठा मुख्य अभियंता अधीक्षण मंत्री कार्यपालन सहायक और उप मंत्री पंछियो के नीचे बैठे निगम के कर्मचारी प्रतिदिन 5 से 10 हजार तकऔर उनको चलने वाले टैंकरो के चालक जल आपूर्ति के नाम पर दो-तीन टैंकर क्षेत्र मे आपूर्ति कर बाकी 15 से 20 टैंकर प्रतिदिन पानी बेचकर 5 से 10000 रुपए दैनिक वेतन भोगी वाले तक कमा लेते हैं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के प्रधान सचिव मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख अभियंता मुख्य अभियंता जहां पुनः घर भ्रष्ट जलशा सोनकारा को सुबह बिस्तर देकर पदस्थ कर दिया गया है। हजारो करोड़ की खरीदी मे 20% एस स्टील के पाइपो उनकी मोटाई दाब का स्तर आदमी डीपी आर्मी और वास्तविक खरीदी मे काफी अंतर होता है के साथ मोटर पंपो विद्युत अपफ के दो आदित्य निर्माण नगर रेखाओ मे भी मोटी कमाई कर लेते हैं और जब इन हरामखोरो से सूचना के अधिकार मे उनके स्टॉक की पंजीकी कॉपी मांगी जाती है तो वीडियो का गृह स्पष्ट लुक देता है हमारे यहां स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नही होता तो तुम्हारे बाप की जागीर है जो सारा धनअपनी मनमर्जी से खरीदी मे लगाओ और सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगने पर स्टॉक के बारे में लिखकर दे दोकि हमारे स्कंद पणजी नही बनाई जाती ताकि मनमाना पाइप सरकारी ढंग से खरीद कर अपने मनमानी तरीके से जलापूर्ति मे लगाओ बैच दो।

कोई कहानी सुनाने वाला नही मुख्य अभियंता कार्यालय मे जहां पर सोलंकी इंदौर मे ही पहले अधीक्षक यात्री भी था और अभी वर्तमान मे भीकुंडली मारे बैठा हुआ है वही हाल इंजीनियर मोनिका मंडलोई का है वही भी10 सालो से ज्यादा समय से इंदौर मे ही दाएं बाएं पदस्थ होती रहती है अधीक्षण यंत्री के रूप मे बैठे एल एन मालवीय को भी इंदौर मे 5 साल से ज्यादा हो चुके है के साथ अजय श्रीवास्तव ने भी इंदौर मे 5 साल से ज्यादा पूरे कर लिए हैं। विद्युत यांत्रिकीय के कार्यपालन यंत्री चेतन रघुवंशी को 15 साल से ज्यादा समय हो चुके हैं। सूचना के अधिकार मे जानकारी मांगने पर और अपील लगाने पर कैसी-कैसियों की जाती है हाल ही मे मैं जनवरी मे एक अभी मुख्य अभियंता कार्यालय मे प्रस्तुत की थी जिस पर इन हरामखोरो ने स्वयं सरकार का दिया हुआ सूचना के अधिकार का पता लगाने का पैसा हजम कर जाने के बाद वहां पर यह नही लिखा कि आवेदन किसके नाम से दिया जाएगा उसका पोस्टल आर्डर किसके नाम से भरा जाएगा और स्वीकारो की फौज ने उसको मनमानी तरीके से रेड करके फाइल कर दिया।

कार्यालय मे जाने पर जब पूछा गया तो यह कहकर कि आपने रु.50 का पोस्टल आर्डर कार्यपाली तियंत्रित के नाम से क्यो नही दिया क्योकि हम उसका भुगतान नही ले सकते हैं तो हरामखोर जलसा जो 19 साल सूचना का अधिकार लगे हुए हो गए सबसे पहले अपने धारा 4 मे आज तक सारी जानकारी सर स्टॉक सारा स्टाफ खरीदी के बिल नाप पुस्तिका आदि की 25 दिनो की जानकारी अपलोड क्यो नही की और फिर जब आपको सूचना अधिकार पता लगाने का पैसा मिला था तो 19 साल के बाद मे शुकरो की फौज बाहर सूचना अधिकार का पटल क्यो नही लगाया और उसका पैसा किसने हजम किया उस सब की भी जांच की जानी चाहिए। ऑफिस अपनी भ्रष्टाचार को कुकर मे को बचाने बिना कोई उचित कारण दिए या आवेदक से पूछे अपील फाइल करके रख दी गई क्यो सब अपने बाप की जागीर है कानून तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। जो बिना ऑफिस मे रद्द करके रख दोगे 19 साल के बाद मे भी जानकारी साइट पर अपलोड नही करोगे क्योंकि गले गले तक लूट भ्रष्टाचार और डकैती मे सभी हिस्सा खा रहे हैं और उसका एक उपाय है कि सबका आखिर चुनावी आचार संहिता के चलते न केवल मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्रियों, का.यं. संजीव श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, चेतन रघुवंशी के साथ अधिकांश सहायक व उप यंत्रियों आदि का जिन्हें 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है। सबका तत्काल ईमानदारी पूर्ण चुनाव करवाने के लिए 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर स्थानांतरण किया जाना चाहिए। क्योंकि यहां पर बैठे सभी सत्ताधीश दल के नेताओ व उम्मीदवार से लेनदेन के सौहाद्र पूर्ण संबंध है।

वही हाल न केवल इंदौर नगर निगम, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, होशंगाबाद, शहडोल, छिंदवाड़ा के साथ पूरे प्रदेश भर के 52 जिलो मे भी अधिकांश निगम पालिकाओ के जल आपूर्ति मे बैठे यांत्रियों का जो वर्षो से कुंडली मारे बैठे हैं तत्काल स्थानांतरण किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचाररोका जा सके चुनाव ईमानदारी से करवाने के साथ-साथ जनता को कम से कमनिश्चित समय पर उचित पेयजल मिल सके। ताकि यह जानबूझकर उचित पंप हाउस का वितरण का नकल भाव नहीं करेंगे आपूर्ति मे व्यथा उत्पन्न कर मोटी कमाई करने का षड्यंत्र करते रहे हैं और करते रहेंगे अब्बा जनता परेशान होकर सड़ा रूट दल के उम्मीदवारो को धकियाने के लिए विवश हो जाएगी। यदि सभी संबंधित अधिकारियो के नीचे से ऊपर तक मात्र उनके द्वारा उपयोग किया जा रहे सभी मोबाइल नंबरो की पुरानी रिकॉर्डिंग निकालकर देख ली जाए। की कहां किसने कितना कैसा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? समझ मे आ जाएगा।

इंदौर मे कई समाचार पत्रों में प्रतिदिन जनता को जलापूर्ति के संबंध मे समाचार छप रहे हैं परंतु किसी को कोई फर्क नही पड़ रहा। जनता परेशान हो रही है गंदे पानी कारण बीमार हो रही है जहां तक जनसंपर्क अधिकारी का सवाल है तो इंदौर मे बैठा हरामखोर पटेल सूचना के अधिकार मे जानकारी तो देता ही नही अपील लगाने पर सुनवाई नही करता और दोनो हाथ से न केवल पत्रकारो का आन वाला शासन से पैसा आजमगढ़ जाता है बल्कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनका भी वाहनो का खाने-पीने टेंट तंबू होर्डिंग बैनर बोर्डस आदि का करोड़ रुपए हजम कर जाता है इसलिए वह सभी विभागो की दैनिक समाचार पत्र मे छपने वाली खबरो पर संबंधित विभागके अधिकारियो से मोटा पैसा वसूल कर कार्रवाई करने की अपेक्षा कुंडली मारकर बैठ जाता है।

सरकार कहे- 'हम डाल-डाल', भ्रष्ट कहें- 'हम पात-पात'

सभी विभागीय साइटों का नियंत्रण रख रखाव निजी क्षेत्र की कंपनियों को

प्रदेश के सभी कार्य विभागों साइटों को हैक करने, निविदा करता द्वारा निविदा ऑनलाइन भरने पर जानकारी एकत्रित करने, जानकारीयां बेचने बांटने जैसा कि पूर्व में लाखों करोड़ के टेंडर घोटाले में जालसाजों के सामने आ चुकी है। पर पूरा कांड दबाया जा चुका है

सभी कार्य विभागों में पूरे प्रदेश में ऑनलाइन और ऑफलाइन का बड़ा घोटाला

मध्य प्रदेश के सभी कार्य विभागो में जो सड़कें भवन पुल तालाब नहरें बांध व अन्य निर्माण रखरखाव मरम्मत आदि के कार्य करती हैं। सभी आपातकालीन कार्य दिखाकर 2 से 20 लाख रुपए तक के टेंडर निकाल अपने खास मुंह लगे नेताओ ठेकेदारो से भरवा अधिकांश काम कागजो पर करवा कर पैसा हजम कर जाती हैं।

इसमें सभी नगर निगम पालिकाएं, परिषद, भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण, जल संसाधन नर्मदा घाटी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय लोक निर्माण विभाग गृह निर्माण मंडल सड़क डकैती विकास निगम, ग्रामीण विकास और उसका ग्रामीण यांत्रिकीय वन, कृषि, उद्यानिकी विभाग सभी विद्युत कंपनियां पुलिस हाउसिंग स्वास्थ्य शिक्षा विभाग कर्मचारी राज्य बीमा निगम, औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम, पशु चिकित्सा आदि सभी कार्य व सेवा विभागों में पिछले 12 साल से इस प्रकार का ऑनलाइन ऑफलाइन का भ्रष्टाचार बहुत खुलकर चल रहा है। आरंभ मे ऑनलाइन के नाम टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज ने सबसे ज्यादा मुफ्त का पैसा ऑनलाइन टेंडर बेचने सेवा शुल्क प्रोसेसिंग शुल्क आदि का अरबो रू बटोर कर ले गई। इसके बारे मे सत्ताधीशों को भी होश नही था होश होगा तो उन्होंने उसमे अपना मोटा कमीशन हजम कर मामले को ठंडा बस्ते मे डाल दिया।

दूसरी तरफ जनता से लूट करने अपने खास ठेकेदारो को ठेके देने के लिए सभी विभाग की सीटों को ऐसे ऑनलाइन सुविधा भरने के समय फर्क जमा करने के समय बंद और खोलने के समय अंतर भी किए जाते हैं और नाम दिया जाता है हैक हो गई। जैसा कि अभी सभी भ्रष्ट विभागो मे जैसे पंजीयन परिवहन निगम और पालिकाएं शिक्षा पर्यटन रेलवे आदि मे भ्रष्टाचार से लूट करने के लिए हैक करने का सारांश लगातार चलता रहता है वही हाल मध्यप्रदेश के अधिकांश विभागो मे भी है।

हर संभाग मे उस संभाग के कर्मचारी बाबू कार्यपालन यंत्री सहायक यंत्रियों उप यांत्रियों के कुछ खास दलाल ठेकेदार हैं। जो सुरा सुंदरी अधिकारियों कर्मचारियों को आपूर्ति करने से लेकर वसूली ऑफलाइन टेंडर जो की 10-20% ज्यादा से लेकर 95% तक अधिक भरकर जिन्हें अधीक्षण यंत्री की सहमति व आदेश पर वहां बैठे संलग्न सहायक यंत्री कुल निविदा की लागत की निश्चित 5 से 10% पर स्वीकृत करते हैं। इंदौर मंडल मे जिसके अंतर्गत 6 संभाग आते हैं। इंदौर एक दो विद्युत यांत्रिकीय अलीराजपुर झाबुआ धार जिनके अधीक्षक यंत्री व्यापमं के सरगना धोर भ्रष्ट रावत हैं। वहां बैठा संलग्न चौरे जो पिछले10 साल से ज्यादा समय से इंदौर मे है सारे ऐसे ऑफलाइन टेंडर 6 संभागों के आपातकालीन व्यवस्था बता, अति विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रम की आड़ मे ऐसे निविदाएं जो 2 से 20 लाख तक की होती है। आंख मीचकर मोटे कमीशन पर स्वीकृत की जा रही है। बेशक यह हाल पूरे प्रदेश के 10 संभागो के मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री कार्यालय मे निश्चित कमीशन पर खुलकर चल रहा है। जिसमें सभी की हिस्सेदारी होने के साथ वह पैसा लोक निर्माण मंत्री मुख्यमंत्री प्रधान सचिव सबको जा रहा है। इसलिए सब इस व्यवस्था को मोटा टुकड़ा हजम कर चुपचाप स्वीकार किए हुए हैं। सारा भुगतान फर्जी बिलो से 50 से 80% कमिशन पर खेल करते हैं। अधिकांश कार्य कागजो पर कर दिया जाता है। जबकि वही टेंडर जब ऑनलाइन लगाए जाते हैं तो 10-20% नीचे से लेकर 80% तक नीचे पर जाते हैं। और इस खेल मे हर संभाग मे करोड़ो रुपए का खेल किया जाता है। बेशक पूरे प्रदेश मे सारे कार्यपालन सहायक मंत्री प्रभारी हैं। जो प्रभार देकर प्रभार लिए हुए मासिक किस्तो का चुकारा करते हुए बैठे हुए हैं।

अब समझा जा सकता है कि जनता का पैसा खर्च होने के बाद मे भी कार्य सही ढंग से क्यो नही होते और वार्षिक भवन जिसमे सरकारी आवास कार्यालय से लेकर न्यायालय उच्च न्यायालय आदि तक के भवन आदि आते हैं पथ जो लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय एवं उप संभागो के अंतर्गत आते हैं। रखरखाव के नाम पर कुल राशि का 10 से 40% छोटे कार्यो का धन इस प्रकार से हर संभाग मे हजम किया जा रहा है यही कारण है की सूचना के अधिकार मे जानकारी मांगने परन केवल कार्यपालन यांत्रिक अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता तक सारे हरामखोर भ्रष्टो की फौज जानकारी देने मे नाटक नौटंकी करती है अपील लगाने पर यह हरामखोर सुनवाई नही करते और सुनवाई करते भी हैं तो सूत्रों की फौज अधिकतम या तो रद्द कर देती है या उल्टी चीज बहाने देकर उलझा देता है सूचना का अधिकार अधिनियम लगे हुए 18 साल गुजर गए परंतु धारा चार की 25 बिंदुओ की जानकारी प्रमुख अभियंता से लेकर नीचे तक किसी भी संभाग उप संभाग मे साइट पर अपलोड नही की ताकि उनके भ्रष्टाचारो के ऊपर किसी की नजर ना पड़े।

श्रीराम ईश्वरीय अवतार हैं या कोई महामानव, इस संदर्भ में लोगों विचारों में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन इस बारे में कोई दो मत नहीं है कि उन्होंने मर्यादा, संस्कारों और मानवीय मूल्यों के जो आदर्श सदियों पहले स्थापित किए, वे आज भी प्रासंगिक हैं। आइए, उनके जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हम सब श्रीराम के चरित्र से प्रेरणा लेकर बेहतर मनुष्य बनने की ओर अग्रसर हों।

मर्यादा-मूल्यों के आदर्श

पुरुषोत्तम श्रीराम

पराक्रमी पुत्र, पितृ आज्ञा के पालक, दुष्टहंता, शोषितों और पीड़ितों के रक्षक, नारी का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने वाले नायक, अपनी प्रजा के भावों को समझने, उन्हें महत्ता देने वाले और अपने न्याय के बल पर रामराज को अक्षुण्ण बनाने वाले राजा थे। उन्होंने बतौर पुत्र, भाई, शिष्य, मित्र, पति और राजा ऐसे आदर्श मूल्य स्थापित किए, जिसके समान कोई अन्य उदाहरण नहीं दिखता है। यही वजह है कि सहस्त्रों वर्ष गुजर जाने के बाद भी श्रीराम के प्रति सम्मान और आस्था का भाव जनमानस में तनिक भी कम नहीं हुआ है। कहना गलत न होगा कि राम का मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप कालातीत है।

रामनवमी विशेष

मात्र दो अक्षर के नाम 'राम' की असीम महिमा सारी दुनिया में व्याप्त है। केवल भारत और हिंदू धर्म में ही नहीं अपितु विश्व के कोने-कोने में राम के नाम की महिमा का गुणगान अलग रूपों या तरीकों से सदियों से होता आ रहा है। राम, जीवन के हर क्षेत्र में समाए हैं। धर्म, दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, राजनीति यानी जीवन-समाज का लगभग हर अंश 'राममय' है। विशेष रूप से भारतीय जनमानस में राम एक ऐसी गहन आस्था का नाम है, जो 'राम नाम जगत आधारा' के भाव में व्यक्त होती है।

तर्क से परे है आस्था

प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल नवमी को आस्थामयी होकर जनसमुदाय श्रीराम का जन्मोत्सव मनाता है। श्रद्धावान राम भक्तों के लिए रामनवमी का यह पर्व, उल्लास, उमंग और अपने आराध्य के महिमामंडन का उत्सव बनकर आता है। राम भक्तों के मन में किसी भी तर्क से ऊपर एक अटूट आस्था वास करती है। राम में उन्हे भगवान के दर्शन होते हैं, मोक्षदायी वैकुंठशायी विष्णु के अवतार दिखते हैं, मर्यादाओं के पुनर्स्थापन की एक दिव्य आशा की किरण नजर आती है। यही वजह है कि श्रीराम को घर-घर पूजा जाता है।

जन्म से जुड़ी पौराणिक मान्यता

भले ही दशरथ पुत्र राम के जन्म और उनके काल निर्धारण पर विद्वान एकमत न हों पर 'सुखसागर' जैसे प्राचीन ग्रंथों में राम का जन्म त्रेता युग में होना माना गया है। उसके अनुसार कलियुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है, जो सबसे छोटा युग है। द्वापर उससे दोगुना और त्रेता उससे भी दोगुना मानते हैं। इस तरह राम आज से कम से कम 12 से 14 लाख वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे। मिथकों और कालगणना के हिसाब से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी राम की जन्म तिथि मानी गई है।

कालातीत मर्यादा पुरुषोत्तम

पौराणिक वर्णन के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम, अपने समय के एक राज्य अयोध्या के राजा दशरथ के

संस्कृति-मूल्यों के प्रतीक पुरुष

आज भी राम का नाम भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों और मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। इसी से प्रेरित होकर आज भी जनसामान्य 'रामराज' की कामना करता है। आज भी राम आदर्श भारतीय समाज के प्रतीक पुरुष हैं। समाज उनमें एक मर्यादा पुरुषोत्तम शासक, लोकरंजक जनकल्याणकारी महान राजा के दर्शन करता है।

करुणावान स्वरूप

पुराणों, मिथकों के अनुसार श्रीराम भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं तो व्यवहारवादियों की नजर में वे एक सर्वगुणसंपन्न आदर्श महामानव हैं। लेकिन हर रूप में वे एक आदर्श जननायक तो हैं ही। 'रामायण' और 'रामचरितमानस' महाकाव्यों में वर्णन किया गया है कि श्रीराम अहिल्या, केवट, शबरी, सुग्रीव, जटायु और विभीषण जैसे समाज के हर वर्ग के लोगों के प्रति समभाव ही नहीं वरन करुणा का भाव भी रखते हैं। तभी तो पक्षीराज जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं करते हैं। शबरी के जूठे बेर भी प्रेमपूर्वक ग्रहण करते हैं। राक्षस जाति के विभीषण और वानर जाति के सुग्रीव को अपना मित्र बनाते हैं। संकटग्रस्त की हर संभव मदद के लिए सर्वदा तैयार रहते हैं। वे जन-जन के शाप, ताप, शोक, भय और हर संताप हरते हैं। इस कथा के अनुसार माना तो यह भी जाता है कि जो भी जाने या अनजाने में श्रीराम की शरण में जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है।

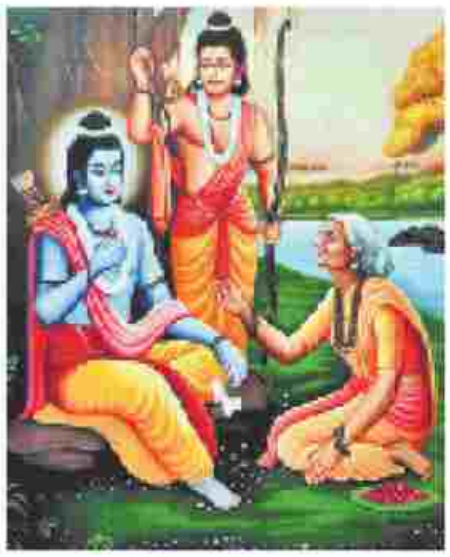

सत्यरक्षक-पराक्रमी-दुष्टहंता

श्रीराम की गुरु भक्ति और समर्पण अद्भुत है। गुरु की आज्ञा पालन वे पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं। यदि वशिष्ठ से वे बचपन में शिक्षा और शास्त्रज्ञान लेते हैं तो विश्वामित्र से वे अल्प समय में ही शस्त्र विद्या न केवल सीख लेते हैं अपितु उसमें इतने पारंगत हो जाते हैं कि उसका उपयोग करके मायावी राक्षसों ताड़का और सुबाहु जैसे आततायियों का नाश कर डालते हैं। श्रीराम दुर्बलों को सताने, मारने तथा उनका शोषण करने वालों को पहले तो सत्पथ पर लाने का प्रयास करते हैं पर, जब ऐसे लोग अत्याचार की सीमा पार करने लगते हैं तब राम दुष्टहंता बन जाते हैं। दूसरों की ताकत को ही अपनी ताकत बना प्रयोग करने वाले दुराचारी बाली का वध करने से परहेज नहीं करते हैं। स्त्री उद्धारक होने के बावजूद, वे स्त्री जाति को बदनाम करने वाली ताड़का और लंकिनी का वध भी करते हैं यानी श्रीराम के लिए न्याय सर्वोपरि हैं।

सब जग चाहे राजा राम

श्रीराम अपने दौर में जाति-पाति तथा ऊंच-नीच से मुक्त राजा हुए हैं। राजा के रूप में राम एक आदर्श स्थापित करते है। वे अपने राज्य की ऐसी व्यवस्था करते हैं कि रामराज्य आने वाले युगों के लिए भी एक आदर्श राज्य बन जाता है। राम स्वयं सादा जीवन उच्च विचार का पालन करते हैं पर अपनी प्रजा को सारी सुविधाएं और सुख देने में कोई कमी नहीं करते। एक समतामूलक, न्यायसंगत समाज की स्थापना करते हैं। छोटे-छोटे संसाधनों का सही उपयोग सीखना हो तो राम आज भी एक आदर्श प्रबंधक दिखते हैं। राम ऐसे दक्ष सेनानायक हैं कि दिव्य अस्त्र, शस्त्रों से युक्त महाबली रावण, उसके मायावी पुत्रों, राक्षसों और लंका की सेना को, महज बंदर, भालुओं की मदद से परास्त कर देते हैं। यही वजह है कि आज भी आमजन अपने शासकों में राम की छवि ढूंढ़ता है और रामराज की कामना करता है।

सारांश यही है कि राम दिव्य महापुरुष, आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन-जन के हृदय में सदियों से विराजमान हैं। राम के चरित्र, कार्यों तथा व्यवहार से युगों-युगों से प्रेरणा ली जा रही है और आगे भी ली जाती रहेगी। *

साहित्य के आदर्श नायक

साहित्य में भी श्रीराम का अनुपम वर्णन मिलता है। राम, संत कबीर के लिए निराकार हैं तो भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास के लिए साकार हैं। वाल्मीकि की प्रेरणा हैं राम तो महाकवि भास और कंबन के कृतिनायक हैं राम। राम के बिना केशव के साहित्य की कोई महत्ता नहीं बचती है। निराला 'राम की शक्ति पूजा' और मैथिली शरण गुप्त अपने महाकाव्य 'साकेत' के माध्यम से आधुनिक युग में राम की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए उन्हे आधुनिक दौर में भी प्रेरक मानते हैं। *

महावीर

अभी के लिए और सभी के लिए हैं

लगभग 2500 वर्ष पहले अहिंसा और सहिष्णुता की शिक्षा देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जीवन ही उनका संदेश है। उनके सिद्धांत और आदर्श वर्तमान संदर्भों में सभी के लिए प्रासंगिक हैं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय आदि अनेक उपदेशों को अपनाकर आज भी रामराज्य की स्थापना की जा सकती है।

वर्धमान महावीर का जन्मदिन महावीर जयंती के रुप मे मनाया जाता है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान आदिनाथ की परंपरा में चौबीसवें तीर्थंकर थे। वे कठोर तप से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर जिन अर्थात विजेता कहलाए। संतों का कहना है कि भगवान महावीर अभी के लिए है और सभी के लिए हैं....

कोई भी सुखी नहीं रह सकता

भगवान महावीर ने कहा था कि दूसरों को दुखी बनाकर कोई सुखी नहीं रह सकता। महावीर से बढ़कर इस जगत में कोई साधना नहीं है। इसमें असीम सुख, शांति और तृप्ति के साथ ही जीवन की ऊंचाइयों और गहराइयों को छूने की शक्ति है।

एक होकर आगे बढ़े जैन बंधु

महावीर जयंती के दिन दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन बंधुओं को एक होकर आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। अपनी मान्यताओं और अपने अहम को ताक में रखकर एक मंच पर आकर समाज कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए।

धन से नहीं मन से धर्म हो

महावीर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। आज धर्म और धर्माचार्यों पर अंगुली उठती है। ऐसे विषम माहौल में समाजजनों को उन लोगों को आगे लाना चाहिए जो सच्चे साधुसंत हैं और नि:स्वार्थ भाव से समाज व धर्म की सेवा कर रहे हैं।

अहिंसा और मैत्री आज की जरूरत

अहिंसा और मैत्री की आज दुनिया को जरूरत है और भगवान महावीर ने यही संदेश दुनिया को दिया था। आज धर्म में दिखावा और आडंबर अधिक आ गया है। अपना नाम गुप्त रखकर गरीबों और पीड़ितों की सेवा करें।

अहिंसा सब समस्याओं का समाधान

विश्व की समस्याओं का एक ही समाधान है- भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना। भगवान महावीर ने कहा था- मैं अपने भक्तों को ही अपनी परतंत्रता से मुक्ति देता हूं। इस स्वतंत्रता का अर्थ हमने बदल दिया।

मैं और मेरा से मुक्त करें अपने को

महावीर सभी के लिए हैं। मनुष्य यदि आज मैं और मेरा- इन दो चीजों से अपने को मुक्त कर ले तो मोक्ष संभव है। बच्चों को हमेशा सुसंस्कार दें। जीवन में पहला स्थान माँ का, दूसरा पिता और तीसरा स्थान गुरु का होता है। त्याग जीवन को उन्नत बनाता है।

अलगाव की नीति खतरनाक

तीर्थंकर महावीर ने विश्व मैत्री का अनुपम सूत्र दिया है। नमक की भांति जियो जो सबका स्वाद बढ़ाता है, शकर की तरह घुल जाओ जो सबको मधुरता देती है और प्राण वायु यानि ऑक्सीजन की तरह जियो यानि सबको जीवन दो। यही भगवान महावीर का संदेश है।

भगवान महावीर : अहिंसा के स्रोत

एक बार तीर्थंकर भगवान महावीर पूर्व की ओर खड़े-खड़े सूर्यदेव का आतप ले रहे थे। इतने में कुछ लोग वहां आए। भगवान महावीर को उस स्थिति में देख उन्हें हंसी आई और उन्हें शरारत करने की सूझी। एक व्यक्ति ने उन पर धूल उड़ाई, किंतु वे आतप में लीन रहे। इस पर दूसरे ने उन पर कंकड़ फेंके किंतु भगवान ने उसकी ओर देखा तक नहीं। तीसरे ने उन पर थूका, लेकिन भगवान शांत ही खड़े रहे। यह देख वे आपस में कहने लगे, अरे! यह कैसा आदमी है, थूकने पर भी इसे क्रोध नहीं आया, न ही इसने हमें भला-बुरा कहा। तब दूसरा बोला, यह तो कोई पागल मालूम होता है या गूंगा। तीसरा बोला,यह तो कोई ढोंगी दिखाई देता है। मैं इसमें गुस्सा लाता हूं। और यह कह उसने उनके सिर पर बहुत सारी धूल फेंक दी किंतु इसका भी उस संत पुरुष पर कोई असर नहीं हुआ।

दीपक जलाएं लेकिन ध्यान रखें...

अग्नि का प्राचीनकाल से ही हर धर्म में महत्व है। अग्नि को प्रत्यक्ष देवतास्वरूप माना गया है। प्राचीन वैदिक धर्म में अग्नि का अत्यधिक महत्व है।

अग्नि का प्रज्वलन देवता की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए हिन्दू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है।

हिन्दू धर्म में प्रत्येक पूजा में दीपक जलाने की परंपरा है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि दीपक प्रज्वलित करने और उसकी दिशा के संबंध में कई नियम बनाए गए है।

तो आइए जानिए कि दीपक की लौ किस दिशा में होनी चाहिए और दीप प्रज्वलित करते समय कौन-से मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए।

दीपक प्रज्वलित करते समय यह मंत्र जपने से सफलता मिलती है -

दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन।
दीपोहरतिमे पाप संध्यादीप नमोस्तुते।।
शुभ करोतु कल्याणमारोग्य सुख सम्पदा।
शत्रुवृद्धि विनाश च दीपज्योति नमोस्तुति।।

- दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है।
- ध्यान रहे कि दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढता है।
- दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है।
- दीपक की लौ कभी भी दक्षिण दिशा की ओर न रखें, ऐसा करने से जन या धनहानि होती है।
- मीन राशि के जातक को चाहिए कि घर की पूर्वोत्तर दिशा में मंदिर बनवाएं।

ध्यान रखें कि घर का मंदिर और रसोईघर साथ-साथ न हो। मंदिर का स्थान परिवर्तन इष्टदेव को प्रसन्न करेगा। लक्ष्मी नारायण की आराधना से भूमि संबंधी लाभ होगा।

घोर निकम्में आलसी मक्कार कांग्रेसियों जागो, सबकी शिकायत करो

बरसों से जमे अधिकारियों-कर्मचारियों का कब होगा स्थानांतरण

- **पत्रकारों का सवाल है तो अधिकांश को महीना मिल रहा है इसलिए वह दूध देती गाय को लात नहीं मारते।**
- **कांग्रेस पार्टी में कांग्रेसियों का मुझे विधायक बना दो मुझे सीएम बना दो मुझे पीएम बना दो लीपने के ना पोतने के, बस पत्रकार ही इनको गाली बक कर जगाएं।**
- **घोर निकम्में आलसी मक्कार पूरे देश के कांग्रेसियों को सब कुछ खटिया पर लेटे-लेटे .चांद तारे देखते हुए सब मुफ्त में चाहिए?**

पूरे प्रदेशके सबसे ज्यादा विभागों में 500 से ज्यादा प्रथम श्रेणी .हजार से ज्यादा द्वितीय श्रेणी अधिकारी तृतीय श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारी की पूरी पूरे प्रदेश में संख्या लगभग 2 लाख से ज्यादा है पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी उनका स्थानांतरण नहीं किया गया था और इस बार भीइन जमे हुए अधिकारी को जिन्हें स्वयं सत्ता के नेताओं ने चुनाव जीतने जल सजानिया करनेविपक्ष कोना सुनने और हाथों सहित करने के लिए ही बैठाया है। आखिर चुनाव आयोग के पास जब पूरे प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की कौन कब से किस पद पर किस जिले में कहां बैठा है की सारी सूची होती है। चुनाव आचार संहिता के चलते 50 से ज्यादा अधिकारी जो इंदौर में बरसों से कुंडली मारे बैठे हैं उनके हरामखोर स्थानांतरण की शिकायत तक नहीं कर पाए।

सबसे पहले नंबर आता है वर्तमान महाजालसाज घोर धूर्त कलेक्टर आशीष सिंह जो वर्तमान में जिला निर्वाचन अधिकारी है। जो कि इसके पूर्व वर्षों तक इंदौर में एसडीएम और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में और बाद मेंनिगम आयुक्त बनाकर बैठ चुका है तो तीसरी बार कलेक्टर बनकर इस हरामखोर जालसा को जिसका पूर्व से ही सभी भाजपा के नेताओं से जो भू. कॉलोनी, वन, भर्ती खनन ड्रग जुआ सट्टा शराब शिक्षा व्यापम कांड सरकारी टेकेदारी माफिया रहे हैं।

उन सब सेन केवल संबंध रहे हैं बल्कि सबसे लेनदेनमी चला रहा है स्वाभाविक है वह निष्पक्ष चुनाव करवाने योग्य नहीं है। तत्काल हटाने की मांग ही नहीं की गई। इसी प्रकार बीएचयू में बैठे कार्यपाली निर्यत्रित संजीव श्रीवास्तव को भी 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। फिर पीएच ई इंदौर संभाग कायर भ्रष्ट डकैत सिहस्थ कार्य सुनील उदिया जो 5 साल से ज्यादा समय से इंदौर ग्रामीण में बैठा है। इंदौर नगर निगम नर्मदा जलापूर्ति में बैठे सभी सहायक यंत्री जनकार्य में बैठे हुए सभी अधीक्षक कार्यपालन सहायक उप यंत्री सब इंदौर में ही वर्षों से कुंडली मारे बैठे सभी नेताओं के पट्ठे बन चुके हैं आखिर इन का स्थानांतरण क्यों नहीं करवाया।

यहां पर बैठा संभाग क्रमांक 2 लोक निर्माण विभाग का सोनी, ई एम बीके जैन, संभाग क्रमांक 1 मनोज सक्सेना, सहायक यंत्री जादौन दुबे सविता वह संभाग क्रमांक 2 विद्युत एवं यांत्रिकी भवन निर्माण सेतु राष्ट्रीय राजमार्ग सबके सहायक यांत्रियों कोजो वर्षों से यहां कुंडली मारे बैठे हुए हैं उन सबको भी हटाया जाना चाहिए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सड़क डकैत विकास निगम में बैठा राकेश जैन इसको भी 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं यह घर भ्रष्ट जिसमें सीनियत में अरबों रुपए का घोटाला कियाबरसों से इंदौर संभाग केआठ जिलो में बैठा हुआ मोटी कमाई करने के साथ सभी के विधायकों सांसदों से इसके पुराने संबंध रहे हैं कब हटाया जाएगा? संयुक्त पंजीयक बीके मोर 2016 से इंदौर में है। सभी 13 उप पंजीयक 3 साल से ज्यादा समय से इंदौर में रहकर भू कॉलोनी माफिया के संरक्षण दाता बनकर बैठे हैं। यही हाल कृषि विभाग में बैठे हुए, कृषि का संयुक्त संचालक आलोक मीणा जिसके पास इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिले हैं। को इंदौर में ही उपसंचालक व संयुक्त संचालक रहते हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उप संचालक एस एस राजपूत सहायक संचालक पाठक संदीप जाट, उपसंचालक परियोजना प्रभारी सरली थॉमस वह अन्य अनेकों, मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में बैठे 25 से ज्यादा महिलाएं और अधिकारी जो सब सहायक आयुक्त के पद से ऊपर हैं बैठे-बैठे 10 से 15 साल हो गए। जिसमें रूबी रघुवंशी वह अन्य उनका स्थानांतरण नहीं किया गया जो सब चुनाव करवाएंगे। इन सब के व्यापारियों कंपनियों के दान देने वाले संचालकों सबसे अच्छे संबंध हैं। खनिज विभाग में बैठा हुआ धर्मेंद्र सिंह चौहान व अन्य निरीक्षक, उद्यानिकी विभाग में बैठा हुआ संयुक्त संचालक जाटव को भी 5 साल से ज्यादा हो गया है। विद्युत मंडल के अधिकांश अप यांत्रिक सहायक यंत्री कार्यपालिका यांत्रिक अधीक्षण यंत्री इंदौर में 5 साल से ज्यादा पूरे कर चुके हैं जो सब चुनाव ड्यूटी में जाएंगे उन सब कुछ हटाया जाना चाहिए वन विभाग में भी एसडीओ गौतम पहले नियमित वन विभाग में था और पिछले कुछ वर्षों से वह सामाजिक वानिकी में बैठा हुआ है। श्रम विभाग में बैठा हुआ घर भ्रष्ट जालसाज लक्ष्मीपति पाठक जिसकी अनेकों सिक्योरिटी एजेंसी में साझेदारी है और आने को विभागों में उसकी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं आखिर इतने लंबे समय से इंदौर में ही क्यों बैठा हुआ है पिछले 15 सालों से इंदौर में ही बैठा हुआ है इसी प्रकार शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग में अनेकों शिक्षक एक ही स्थान पर 5 वर्षों से विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन के बहाने जमे हुए हैं। परिवहन सहकारिता मत्स्य पेंशन पुलिस कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रदूषण जेल उद्योग महिला बाल विकास, खाद एवं औषधि, कोषालय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग शहरी विकास में बरसों से बैठे अधिकारी कर्मचारी जो सब चुनावी कार्य करेंगे सबका तत्काल स्थानांतरण किया जाना चाहिए। यह सूची कांग्रेस के पदाधिकारीयों को एकत्रित करके तत्काल भारतीय व मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त को भेज सबका स्थानांतरण करवाना चाहिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय के मुख्य अभियंता कार्यालय में बैठा हुआ प्रभारी मुख्य अभियंता सोलंकी जो पहले भी इंदौर में अधीक्षक यंत्री के पद पर मुसाखेड़ी में बरसों तक बैठ चुका है। व अधीक्षक यंत्री कार्यालय के का.यं. व सहायक यंत्रियों के साथ, मुअ कार्यालय के अधीक्षण यंत्री एल एन मालवीय, कार्य. मोनिका मंडलोई व संलग्न सहायक यंत्री के कार्यपालिका नीतियों के साथ अधिकांश स्टाफ घोर जालसाज व मक्कार है। वर्षों से कुंडली मारे बैठा हुआ है। बाबूओं से लेकर ऊपर तक सबका स्थानांनतारण चुनाव आचार संहिता में तत्काल किया जाना चाहिए। मुख्य अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग में भी संलग्न सहायक यंत्री अशोक जैन जो पिछले 15-20 सालों से, अधीक्षण यंत्री कार्यालय में बैठा चोर 8 साल से इंदौर में ही है। तत्काल स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जहां तक नगर निगम का सवाल है तो वहां तो सैकड़ों कर्मचारी-अधिकारी जो दूसरे विभागों से प्रतिनिधि पर आए थे बरसों से कुंडली मारे बैठे रहकर चौक सबसे लूट व लुटा रहे हैं। निगम के पशु चिकित्साविभाग के चिड़ियाघर के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव को बैठे हुए भी 15 से ज्यादा वर्ष बीत गए जो चिड़ियाघर के चिड़ियों के दाने में डकैती डालने से लेकर बड़े वन पशुओं जिसमें हाथी-शेर आदि तक के भोजन में से हर महीने लाखों रुपए की मोटी कमीशन खोरी में हजम कर जाते हैं इन्ही के कार्यकाल में अनेकों शेर बब्बर शेर तेंदुए आदि की मौत हुई है। परंतु मुख्यमंत्री का रिश्तेदार होने के कारण कोई हटाने की हिम्मत नहीं कर सकता तो यह आखिर चुनाव नहीं करवाएंगे या प्रभावित नहीं करेंगे जो उनको नहीं हटाया जा रहा।

10 साल में झूठे वादों से जीत जनता व देश को तबाह किया

पेज 1 का शेष

चुनाव जीत गया तो सबके कपड़े उतार कर रिलायंस के प्लास्टिक के कटोरे थमाएगा। जिसमें भीख भी नहीं मिलेगी क्योंकि सारे बड़े सनातन तीर्थ क्षेत्रों भिखारी के गिरोह के सरगना भी इन्ही वाचाल डकैतों के हैं। तो वहां भिखारी बन भीख भी नहीं मांग पाओगे।

मोदी की गारंटी के साथ 2024 का घोषणापत्र

लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा अपने चुनाव घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से जारी करती है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में बीजेपी **'GYAN'** यानी गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी शक्ति पर फोकस किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र की थीम है 'बीजेपी का संकल्प, मोदी की गारंटी'

तीन करोड़ घर बनाने का संकल्प

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ घर और बनाने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर-घर पहुंचाए हैं, अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर-घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। भारत आज दसह त नत्वज्जहू मे दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष, नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारीशक्ति की नई भागीदारी के होंगे।

70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा

पीएम मोदी ने कहा, अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल से ऊपर का हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या फिर उच्च मध्यम वर्ग से ही क्यों न हो, उन्हें 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा 'जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूजता है। यही सबका साथ, सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है... भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है।'

मुद्रा योजना के तहत मिलेगा 20 लाख रुपये का लोन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र 'संकल्प पत्र' जारी होने पर कहा, 'बीते वर्षों में करोड़ों लोगों को उद्यमी बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है...इस सफलता को देखते हुए भाजपा ने एक और संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपये हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का इरादा किया है... '

5 साल तक जारी रहेगी मुफ्त राशन योजनाः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में बताते हुए कहा, 'पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है। इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मेनिफेस्टो की सुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ - युवाशक्ति, नारीशक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस **dignity of life** पर, **quality of lives** और निवेश से नौकरी पर है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषणयुक्त हो, उसके मन को संतोष देने वाली हो और अफोर्डेबल हो, सस्ती हो।'

चुनावी चंदे पर नया खुलासा!

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 3 दिन पहले सरकार ने दी 10 हजार इलेक्टोरल बॉन्ड छापने की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक करार देने से तीन दिन पहले ही वित्त मंत्रालय ने 10,000 बॉन्ड की छपाई को मंजूरी दी थी. मंत्रालय की ओर से एसपीएमसीआईएल (सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) को 1 करोड़ रुपये की मूल्य के 10,000 चुनावी बांड की छपाई के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई थी.

रिपोर्ट में दावा किया गया कि वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दो सप्ताह बाद 28 फरवरी को भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बांड की छपाई पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 हजार बॉन्ड की छपाई की मंजूरी 12 फरवरी 2024 को दी गई थी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 27 फरवरी को वित्त मंत्रालय की ओर से एसबीआई और दूसरे लोगों को ईमेल भेजा गया था. जिसमें चुनावी बॉन्ड की छपाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था. चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी को यह जानने का पूरा हक है कि राजनीतिक पार्टियों को कहां से चंदा मिल रहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था. चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक किया था. चुनाव आयोग ने सारा डेटा दो सेट में अपलोड किए थे. पहली लिस्ट में कंपनियों की ओर से खरीदे गए बॉन्ड की जानकारी थी और दूसरी लिस्ट में राजनीतिक पार्टियों की ओर से बॉन्ड भुनाने वाली जमा राशि की जिक्र था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर एसबीआई से पूछा कि उसने चुनावी बांड नंबरों का खुलासा नहीं किया है. कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई को यूनीक नंबर का खुलासा करना चाहिए, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य है.

सर्वोच्च न्यायालय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के घातक और मिलावटी पदार्थों पर भी रोक लगाए

पेज 8 का शेष

इसे लेकर भी कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की कि हर विद्यमान कानून का सम्मान होना चाहिये, चाहे वह किसी भी अदालत का हो। न्यायालय ने कहा कि दोनों ने (रामदेव-बालकृष्ण) हर सीमा लांघ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दोनों को अदालत में दिये गये आश्वासनों का पालन करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की गाज केन्द्र पर भी गिरी। अदालत ने आश्चर्य जताया कि जब पतंजलि कोविड के दौरान बाज़ार में यह कह रही थी कि उसका (कोरोना) एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, तब केन्द्र क्यों आंखें बंद रखे हुई थी। उल्लेखनीय है कि 2011 के अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए लोकायुक्त आंदोलन में और भी ज्यादा लोकप्रियता बटोरकर तथा भाजपा सरकार की शह पाकर एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने वाले रामदेव अपने विवादास्पद बयानों एवं गतिविधियों के लिये जाने जाते हैं। कांग्रेस के डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले कार्यकाल में रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े हंडाबरदार बन गये थे। उन्होंने ही दावा किया था कि विदेश में रखा काला धन आने पर लोगों से टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी और पेट्रोल 35 रुपये प्रति लीटर मिलने लगेगा। यह अलग बात है कि पिछले दस वर्षों से योगाचार्य इस मामले में मौन धारण किये हुए हैं। स्वदेशी उत्पादों तथा परंपरागत चिकित्सा पद्धति का राग अलापने वाले रामदेव ने बाजार के रूझान को देखते हुए वे सारी चीजें बनानी व बेचनी शुरू कर दी जो आधुनिक जीवन पद्धति के हिस्से हैं। इनमें तरह-तरह के सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर खाद्य सामग्रियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, कंपनी मैगी जैसे पदार्थ भी बनाने लगी जो विदेशी व्यंजन तो है ही, स्वास्थ्य के लिये बेहद खतरनाक भी हैं। आज भारत का शायद ही कोई शहर होगा जहां पतंजलि उत्पादों की बिक्री न होती हो और कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां पतंजलि द्वारा निर्मित किसी न किसी उत्पाद के उपभोक्ता न हो। वैसे यह भी जानना ज़रूरी है कि पतंजलि के ज़्यादातर उत्पाद गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में आज जो रामदेव अपने सहयोगियों के साथ कानून के सामने शीर्षासन करते नज़र आये, उन्होंने भारत के लोगों का कोरोना काल में बड़ा अहित किया था। एक तो उनके कारण बड़ी संख्या में लोगों का भरोसा वैज्ञानिक तरीकों से तैयार की गई संक्रमणरोधी दवाओं पर से विश्वास उठ गया तथा उसके एवज में पतंजलि ने आनन-फानन में तैयार की गई दवा का बड़े पैमाने पर निर्माण कर बाज़ार में खूब पैसा कमाया। पर्याप्त प्रयोगों व उनके परिणामों की वैज्ञानिक जांच के बिना कोई भी दवा लाभ की बजाय नुकसानदेह ही होती है पर रामदेव ने अंग्रेज़ी दवाओं को बेकार बतलाते हुए लोगों को बरगलाया भी था।

दूसरे पहलू पर भी नजर डालें

जितनी भी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां है जो 24 घंटे विज्ञापन देकर देश की जनता से चाहती हैं,कवि ब्रश और प्रेस लेकरमुंह मेंथुमते रहेचाहे उसे डांट ही क्यों टूट जाए और व्रत सेवांत साफ करने परकारोबार दिनों दिन फल फूल रहा है उस पर यह देश के किसी भ्रष्ट जालसाज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हिस्सों पर नाचने व दुकानदारी चलाने वाले गैर सरकारी जनहितकारी संगठन ने आवाज उठाई या सर्वोच्च न्यायालय ने कभी आगे बढ़करजनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वसंज्ञान लिया।

सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां का पैकेजिंग फूड और पेय पदार्थों जिनमें कीटनाशकों व संरक्षित करने जो रसायन होते हैं जनता में बीमारियां फैलाने के साथ अपने प्लास्टिक व पैकेजिंग के कचरे से प्रदूषण फैलाकर धरती की जलवायु से लेकर जल थल मानव से लेकर सभी पशु पक्षियों कीटों वनस्पतियों को बर्बाद कर पूरी धरती को मरुस्थल बनाने का कार्य रहे हैं। उनके ऊपर कभी थोड़ा स्वसंज्ञान लेकर आवाज उठा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम06 को रद्द करवाने जो जनता को लूटने के लिए हर खाद्य पदार्थ को प्लास्टिक से पैकेट करने के लिए बाध्य करता है। केंद्र सरकार को नोटिस दिया जिस देश में यह बकवास की कंपनियों की पैकेजिंग और 10 करोड़ छोटे दुकानदारों देखो खत्म कर शॉपिंग मॉल चलाने बेरोजगारी भुखमरी और बीमारियां फैला रहा है। इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वसंज्ञान लेना चाहिए।

सभी कंपनियां फर्जी विज्ञापनों के दम परअपना घातक कीटनाशक वी संरक्षित करने वाले रसायन युक्त खाद्य पदार्थ एवं अन्य सामग्री बेच मोटा मुनाफा कमा सत्ताधीशों को पैसा बांट 40 सालों से फर्जी विज्ञापनों के दम पर तांडव कर रही है। उनके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने कभी उंगली उठाई।

बेशक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पहले हुए गैर सरकारी संगठन उनके वित्तीय सहयोग से चल रही उनके व्यावसायिक सहयोग के लिए देसी व्यवसाईयों को नष्ट करने का षड्यंत्र का हिस्सा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले ही लिया है तो सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पारले हिंदुस्तान युनिलीवर इंडियन टोबैको कंपनी अमूल चॉकलेट बिस्कुट बनाने से लेकर अन्य प्रकार की खाद्य पदार्थों को पैकेजिंग में बेचने वालों के खिलाफ आवाज उठाई ही जानी चाहिए और उनको वंडित करखाद्य पदार्थ में मिलाई जा रहे कीटनाशक और संरक्षित करने वाले रसायनों को रोककर देश की जनता की भविष्य को स्वस्थ एवं सुरक्षित बनाए जाना चाहिए।

बाबा रामदेव जी को लपेटती सुप्रीम कोर्ट ने कभी सलमान खान से पूछा कि वह ड्यू पीकर पहाड़ी से कैसे कूद जाते हैं

अगर ड्यू पीकर सलमान खान विडियो बना कर कूद सकता है तो

पेप्सी कंपनी वालों को ड्यू पिलाकर पहाड़ी से कुदाया क्या

कभी अमिताभ बच्चन से पूछा है कि कैडबरी से ही दिपावली क्यों मनाएं

क्या इसे भारतीय मिठाई या घर के पकवान का मजाक उड़ाते नहीं माना जाए

सुप्रीम कोर्ट ने कभी Pollycab कंपनी से पूछा है कि उसके वायर से ही 25% बिजली की बचत कैसे होगी

और अगर नहीं होती है तो उसे जेल क्यों नहीं

कभी शाहरुख खान अजय देवगन से पूछा है कि वह विमल गुटखा कितना खाते हैं

और विमल पान मसाला केसर का मजा नहीं मुख रोगों की सजा क्यों देता है?

तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि शाहरुख खान अजय देवगन को कोर्ट में खड़े कर केसर का स्वाद दिलाकर देखा जाए

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर बाबा रामदेव को ही पूछ रही है कि आपके विज्ञापन के परिणाम स्वरूप उत्पाद नहीं है तो आप जेल जाओ

क्या यह सुप्रीम कोर्ट का भारतीय संस्कृति को जागृत करने और विदेशी कंपनियों की लूट खसोट से बचाने वाले एक भारतीय के विरुद्ध दण्ड है

अगर दण्ड है तो सबके साथ क्यों नहीं?

बाबा रामदेव तो विज्ञापन करें तो 100% की गारंटी दे अन्यथा जेल

लेकिन विदेशी कंपनियों पर यह लागू नहीं है

यह सुप्रीम कोर्ट का भारतीय व्यापारियों या भारतीय संस्कृति के पैरोकार के साथ ही पक्षपात तो नहीं?

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कठपुतली विश्व घातक संगठन कर रहा पर्यावरण बर्बाद

पेज 8 का शेष

दूसरी तरफ यह सच न केवल अमेरिकी और यूरोप के साथ एशिया और भारत का मीडिया क्यों नहीं छत और यदि सचमुच पर्यावरण की इतनी चिंता है तो विश्व घातक संगठन को सबसे पहले अपने षड्यंत्रकारी सदस्यों की मोटी कमाई और पूरी दुनिया को नियंत्रित करके नोचने की लालसा में विश्व के अधिकांश देशों में थोपे गए खाद्य वस्तुओं औषधियों की पैकेजिंग के कानून को खत्म क्यों नहीं किया जाता।

बेशक यह सत्य एक दिन स्वीकार करना पड़ेगा और दुनिया से खाद्य वस्तुओं और औषधीय को प्लास्टिक पैकेजिंग से मुक्त करने का अभियान स्वयं ही पूरी दुनिया में चलना पड़ेगा अन्यथाइस शताब्दी के अंत तक पूरी दुनिया प्लास्टिक की कचरे से ढक जाने के कारण मानवों के रहने योग्य नहीं रह जाएगी। इस तिथि को अभी समझ ले तो बेहतर होगा अन्यथा धरती से न केवल मानव बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों जलीय जीवन भी नष्ट हो जाएगा।

19 राज्यों के ऑडिट में, सात नागरिक समाज संगठनों ने लोकप्रिय एफएमसीजी ब्रांडों का एक समूह पाया है - जिनमें पारले प्रोडक्ट्स, आईटीसी, ब्रिटानिया, हल्दीराम, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मिल्की मिस्ट और यूनाइटेड स्पिरिट्स शामिल हैं - जो भारत के शीर्ष प्लास्टिक प्रदूषकों में से हैं।

रिपोर्ट 18 नवंबर को जारी की गई थी। 'ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक' नामक वैश्विक समूह का हिस्सा, छह संगठनों के 1,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने ऑडिट किया, जिसमें दो स्रोतों - घरों और सार्वजनिक स्थानों से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करना शामिल था। कुल मिलाकर, उन्होंने 1,49,985 टुकड़े एकत्र किए, जिनमें से 61% का उपयोग कथित तौर पर खाद्य पैकेजिंग के लिए किया गया था (और इसमें से 25% अकेले दूध के लिए था)। लगभग 18% का उपयोग पैकिंग प्लास्टिक सामग्री के रूप में, 8% का व्यक्तिगत देखभाल में, 7% का उपयोग घरेलू उत्पादों के लिए और 1% का उपयोग धूम्रपान सामग्री के रूप में किया गया था।

रिपोर्ट में शामिल शीर्ष 10 अंतरराष्ट्रीय कंपनियां यूनिलीवर, पेप्सिको, कोका कोला, नेस्ले, अमेज़ॅन होल फूड्स, रेकिट बेंकिज़र, कोलगेट पामोलिव, पी एंड जी, क्राफ्ट हेंज और मोंडेलेज़ इंटरनेशनल हैं।

यह ऑडिट का चौथा वर्ष था। इनमें से कुछ ब्रांड पहले भी शीर्ष 10 में शामिल हो चुके हैं।

एक चिंता की बात यह है कि इनमें से अधिकांश टुकड़े (35%) बहुस्तरीय प्लास्टिक थे - जिन्हें व्यावसायिक स्तर पर पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। यानी ये सिंगल-यूज़ हैं, वे पाउच, पैकेट, रैपर आदि के रूप में आते थे - साथ ही टूथपेस्ट ट्यूब और सिगरेट बट्स में भी। इन्हें पहली बार में अलग करना और इकट्ठा करना भी मुश्किल होता है।

हालाँकि, डिस्पोजेबल कटलरी में बहुस्तरीय प्लास्टिक नहीं होता है - लेकिन इसे आमतौर पर पुनर्नवीनीकरण भी नहीं किया जाता है। अन्य 31% कम घनत्व वाली पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन थे, जो हमेशा पुनः प्रयोज्य नहीं होते हैं। वे दूध के पैकेट, क्लिंग रैप, प्लास्टिक की बोतलें, निचोड़ की बोतलें, प्लंबिंग पाइप और वायर इन्सुलेशन के रूप में आए।

जिन वस्तुओं को व्यापक रूप से पुनर्चक्रित किया जा सकता था और जो ऑडिट स्थलों पर पाई गईं, उनमें शैम्पू, तेल, डिटर्जेंट, सोडा और तरल दवाएं (सिरप, आदि) जैसे उत्पादों को रखने के लिए उपयोग की जाने वाली बोतलें शामिल थीं। रिपोर्ट के अनुसार, इन उत्पादों को डाउन-साइकिल करने से पहले कुछ बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है, जिसके बाद वे पर्यावरण में लीक हो जाते हैं और प्रदूषण बन जाते हैं।

खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली कम घनत्व वाली पॉलीथीन और पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक रीसाइक्लिंग स्ट्रीम में खारिज कर दी जाती है, खासकर छंटाई के स्थान पर, क्योंकि फेंके जाने के समय वे गीले कचरे से दूषित हो जाते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 कहते हैं कि प्लास्टिक उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों को उनकी तथाकथित 'विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी' के हिस्से के रूप में, अपशिष्ट प्रबंधन का स्वामित्व लेना चाहिए। इस प्रतिमान में, नियमों की परिकल्पना की गई है कि बहुस्तरीय प्लास्टिक, जिसे पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, को कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

2018 में, केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन करने और ब्रांड-मालिकों की जिम्मेदारियों को आसान बनाने का निर्णय लिया। परिवर्तन में कहा गया है कि केवल बहुस्तरीय प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना होगा, खासकर यदि इसे किसी प्रकार की उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या अन्य उपयोगों के लिए इलाज या पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, बहुस्तरीय प्लास्टिक वाली अधिकांश वस्तुएं जो 'विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी' के दायरे में आती हैं, उन्हें या तो भस्म करने के लिए नामित किया जाता है या किसी अन्य प्रकार के अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों में ले जाया जाता है। हालाँकि, यह पुनर्चक्रण नहीं है - इस तथ्य के बावजूद कि भारत में कार्यात्मक अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के अधिकांश प्रयास असफल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, 'हाल के वर्षों में, कॉर्पोरेट कंपनियां बहुस्तरीय प्लास्टिक के समाधान के रूप में भस्मीकरण, रासायनिक रीसाइक्लिंग और बायोप्लास्टिक्स को वैध बनाकर अपनी छवि को हरा-भरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं।'

रिपोर्ट का अनुमान है कि भस्मीकरण - या तो अपशिष्ट-से-ऊर्जा या प्लास्टिक-से-ईंधन के रूप में - संसाधित प्रत्येक टन प्लास्टिक के लिए तीन टन CO_2 जारी करता है, इसके अलावा कार्सिनोजेनिक पदार्थ भी उत्सर्जित होते हैं। रिपोर्ट में रासायनिक पुनर्चक्रण के आकलन को भी कहा गया है - यानी, रासायनिक रूप से प्लास्टिक पॉलिमर को मोनोमर्स में तोड़ना और नए पॉलिमर बनाने के लिए मोनोमर्स का पुनः उपयोग करना - 'कुख्यात भ्रामक'।

रिपोर्ट के अनुसार, 'कंपनियों को इन कम मूल्य और गैर-पुनर्चक्रण योग्य एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए अपनी पैकेजिंग और डिलीवरी सिस्टम को फिर से डिज़ाइन करने और टिकाऊ पुनः उपयोग और रीफिल डिलीवरी सिस्टम में निवेश करने की आवश्यकता है।'

पुणे में कचरा बीनने वालों के साथ काम करने वाली संस्था स्वच्छ एलस की प्रोजेक्ट मैनेजर और इसकी प्रमुख लेखिका लुबना अनंतकृष्णन कहती हैं, 'केवल एक ही समाधान है - जो ऐसे प्लास्टिक के उत्पादन को कम करना है जिनका बड़े पैमाने पर पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है।' रिपोर्ट, द वायर साइंस को बताया गया। 'पुनर्चक्रण के लिए सुझाई गई प्रौद्योगिकियाँ बड़े पैमाने पर टिकाऊ नहीं हैं। और इसे कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।'

विश्व भर में कचरे के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां व विश्व घातक संगठन जिम्मेदार

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कठपुतली विश्व घातक संगठन कर रहा पर्यावरण बर्बाद

भारतीय प्रसार माध्यम न चले भेड़ चाल जांच परख कर सच छापे

भारतीय मीडिया मुद्रित समाचार पत्र एवं टीवी चैनल जहां पर भानु बड़ों की फौज है ज्यादा पढ़ी-लिखी नही होती इसीलिए बिना सच को खोज परखे विदेशी प्रसार माध्यमों जो स्वयं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रखवले हैं, की नकल कर सच्चाई से दूर अपने ही देश को बदनाम करने से नही चूकते।

13 अप्रैल को अधिकांश समाचार पत्रों में भारत को विश्व में प्लास्टिक कचरा फैलाने के लिए जिम्मेदारों में 12 देश की श्रेणी में रखा गया है जबकि सच इसके विपरीत अकेले कोका- कोला को ही ले तो वह दुनिया में सबसे ज्यादा 120 000 टन प्लास्टिक कचरा अपने घातक बीमारी वर्धक शीतल पेय की बोतलों के माध्यम से पृथ्वी पर कचरे के रूप में फिंकवाता है। आखिर विश्व घटक संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस और उसके सारे सदस्य जो सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सारे पद नियुक्त कमीशन खोर नाचने वाले बिके हुए हैं। वह हरामखोर जालसाजो निखट्टू और निकम्मे लालचियों की फौज कभी नही बताती तो जितने भी विश्व में शीतल पेय के नाम से शक्कर कीटनाशक कैफीन वह अन्य रसायन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जिसे मानव ही नही हर जीव अपने श्वसन उत्सर्जन में त्यागता है। जिससे हर साल ज्यादा पीने के बाद उसमें घुली कार्बन डाइऑक्साइड पेट में पहुंचकर तत्काल ना निकल सकने के कारण सीधे ही पूरे विश्व में हजारों लोगों की मौत हो जाती है जिसे छुपा लिया जाता है। इसके साथ ही बच्चों से लेकर गुना तक ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त सारे पे जिसमें कोका-कोला सबसे अग्रणी है पेट में पहुंचकर अनेकों बीमारियों को जन्म देती है। विश्व घातक संगठन और विश्व के अनेकों विश्वविद्यालयों स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा जाने के बाद में भी आखिर वह नीचे बीडियो का विश्व का सबसे गंदा खतरनाक जालसाजी अमेरिकी विश्व घटक संगठन जो अपने आप को विश्व स्वास्थ्य संगठन बताता है क्यों नही रोकता ऐसी घातक पेय पदार्थों को जो मानव स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं। पर वह अमीरकी वर्ण संकर जो स्वभाव से ही घर नीचे घातक निर्दयी होते हैं। एक तरफ ऐसी घातक पेय पदार्थ बेचकर मोटी कमाई करते हैं तो दूसरी तरफ यही घातक पेय पदार्थ जो घातक बीमारियां बनते हैं उनको ठीक करने के लिए वही वर्ण संकर घातक अमेरिकी दवा उत्पादक कंपनियां उसकी मोटी कमाई करने के लिए दवाइयां भी मोटी कमाई पर बेचते हैं। फिर अमेरिकी वॉलमार्ट अमेजॉन ने भारत में मोटा पैसा खर्च करके जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का कानून बनवाया उसमें ही तो अपनी मोटी कमाई करने व प्लास्टिक पैकेजिंग में पैकेज्ड फूड खाद्य पदार्थों में घातक कीटनाशक एवं के लिए भारत में सबसे ज्यादा फूड पैकेजिंग में रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी से निकले पेट्रो निक्षेपों से बने प्लास्टिक पॉलिथीन का पैकेजिंग उपयोग करने वाली कंपनियां में आईटीसी हिंदुस्तान लीवर पार्ले रिलायंस टाटा मित्तल आदि खाद्य पदार्थों पेय पदार्थों की पेकेजिंग में उपयोग करने वाली कंपनियां है जो सब सरकार कोन केवल इलेक्ट्रॉन बंद खरीदनी है पीएम केयर फंड में देती हैं और चोरी छुपे मोटा चंदा भी देती है तभी वह व्यापार कर पाती है परंतु उनका वही प्लास्टिक दुनिया में हमारी बदनामी का और पर्यावरण की बर्बादी का कारण बनता है। इसके बारे में सरकार उसका खाद्य एवं औषधि विभाग, केंद्रीय प्रदूषण मंडल, वन एवं पर्यावरण, शहरीय एवं ग्रामीण मंत्रालय जहां पर जनता इनका उपयोग करके कचरे के रूप में फेंकती व प्रदूषण फैलाती हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सभी मंत्रालयों के मंत्री प्रधान सचिव से नीचे तक के अधिकारी एवं कर्मचारी चुप रहते हैं। जो सबसे ज्यादा मृदा और जल को प्रदूषित करने के साथ वायुमंडल को भी प्रदूषित करके पृथ्वी के जल स्रोतों को बर्बाद करने से लेकर वनस्पतियों वी पशु पक्षियों का जीवन नष्ट करने पर तुले हैं। यह हाल भारत चीन जहां दुनिया की 40% आबादी रहती है। के साथ अमेरिका रूस ब्रिटेन ब्राजील मेक्सिको वियतनाम ईरान इंडोनेशिया मिश्र और तुर्की आदि आते हैं पर वहयथार्थ में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के घोर लालच, मोटी कमाई, बीमारी फैलाने के षड्यंत्र के कारण पूरी दुनिया में प्रदूषण फैलाकर पर्यावरण बर्बाद करने पर तुले हैं आखिर विश्व घातक संगठन के सूकरों और गिद्धों की फौज स्वयं यह स्वीकार क्यों नही करती।

(शेष पेज 7 पर)

सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को पिलाया कानून का काढ़ा

योग गुरु के रूप में मिली लोकप्रियता के सहारे आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण एवं बिक्री का पतंजलि के नाम से बड़ा व्यवसायिक साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबा रामदेव तथा उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने कानून के महत्व तथा ताकत का एहसास कराया। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान उनके द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के लिये जमकर फटकार तो लगाई ही, उन्हें इसके परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चेताया कि उनके खिलाफ़ झूठी गवाही का मामला भी बनता है।

अदालत ने केन्द्र को भी नही बख्शा जो पतंजलि के झूठे विज्ञापनों की ओर से आंखें बंद किये बैठी रही। सुप्रीम कोर्ट का लहज़ा इतना सख्त था कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में बढ़े रामदेव एवं बालकृष्ण दोनों ही माफ़ी मांगते नज़र आये।

मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पिछले वर्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसमें पतंजलि के इस दावे को गलत बताया था कि योग अस्थमा व डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। इसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को निर्देश दिया था कि वह कोई भी भ्रामक विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित न करे। नवम्बर, 2023 में पतंजलि की ओर से दायर शपथ पत्र में ऐसा करने का आश्वासन दिये जाने के बावजूद कंपनी की ओर से विज्ञापन दिये जाते रहे। उस सुनवाई में कंपनी के वकील द्वारा भी निर्देशों के पालन का भरोसा जताया गया था। इतना ही नही, रामदेव-बालकृष्ण की ओर से इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। यह बात कोर्ट के संज्ञान में आई और पतंजलि को जारी नोटिस की मंगलवार को हुई सुनवाई में दोनों को फटकार लगाई गई।

कोर्ट ने नाराज़गी जतलाई कि एक ओर तो पतंजलि अपने दायर हलफनामे में माफी मांग रही है, वही वह भ्रामक विज्ञापन भी जारी कर रही है। इतना ही नहीं, उसकी ओर से मीडिया कॉन्फ्रेंस भी की जाती है। यह माफी मांगने का तरीका बिलकुल नही है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 अप्रैल को मुकर्रर की है जिसमें दोनों को फिर से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।

साथ ही केन्द्र को भी नोटिस जारी की गई है।सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली एवं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस बात पर भी नाराज़गी व्यक्त की कि अपने हलफनामा में पतंजलि ने कुछ ऐसे दस्तावेज जोड़े है जो सुनवाई के बाद की तारीखों के हैं। इसलिये इसे झूठी गवाही और गलत हलफनामा दायर करने का भी मामला बतलाते हुए दोनों को आगाह किया कि वे इसके परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहें। देखना यह है कि आगामी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है।

अपने हलफनामे में पतंजलि के इस कथन से भी कोर्ट नाराज़ था जिसमें कहा गया था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स (मैजिक रेमेडीज़) एक्ट काफी पुराना हो गया है।

(शेष पेज 7 पर)

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों
उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों
ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी
विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के
विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व
samaymaya.com की वेबसाइट पर
समाचार, शिकायतें और विज्ञापन
(प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें

मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है
एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादक: अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958